

सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

» Pg12
योगी सरकार
ने चिकित्सा
शिक्षा
प्रशिक्षण को
दिये 423.80
करोड़



कानपुर, सोमवार, 22 दिसंबर, 2025

वर्ष: 02, अंक: 340, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

इनसाइड बांग्लादेश हिंसा पर कानपुर में मोहमद यूनुस का पुतला...» Pg02

पोस्टर-बैनर लेकर सपा का सड़क से सदन तक प्रदर्शन कोडीन कफ सिरप पर बवाल योगी के हमले से भड़की सपा

विधानसभा में छिड़ा शीत युद्ध: पूरे देश में दो नमूने हैं कहने पर
विपक्ष का वाकआउट, सीएम बोले यूपी में एक भी मौत नहीं!

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सपा ने कफ सिरप पर चर्चा की मांग की और वेल में चले आए। स्पीकर सतीश महाना ने चेतावनी देकर सभी को समझाया और प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसी दौरान सीएम योगी के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा ने वाकआउट भी किया।



दरअसल कफ सिरप पर ही पूछे गए सवाल पर सीएम योगी ने कह दिया कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से इंग्लैंड के सैर सपाटे पर जाएंगे और आप चिल्लाते रहेंगे। योगी ने भले किसी का नाम नहीं लिया लेकिन सपा नेताओं ने इसी पर हंगामा शुरू कर दिया और विधानसभा से वाकआउट कर गए। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने मांग की कि इसमें शामिल सभी को गिरफ्तार किया जाए। राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराये और दोषियों को जेल भेजे।

स्पीकर की चेतावनी के बाद माने सपा विधायक

इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडीन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। सरकार ने मामले में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। इससे

विधायक और भड़क गए और मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ गए। सतीश महाना ने भी कहा कि सरकार ने बता दिया है कि कोडीन सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ तो चर्चा कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट पाऊंगा। उन्होंने सपा के विधायकों से वेल से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया। इसके बाद विधायक अपनी-अपनी सीट पर लौट गए। तब जाकर प्रश्नकाल शुरू हुआ।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी कैंट से सपा नेता अमित यादव के कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के कारोबारी



संबंध हैं। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर की सलाह से कफ सिरप हर व्यक्ति लेता है। कोडीनयुक्त सिरप से मौतों के मामले अन्य राज्यों से आए हैं। यूपी में यह प्रतिबंधित है। प्रदेश में मौत के मामले सामने नहीं आए हैं।

आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे

सीएम योगी ने कहा कि 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने भी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। अब तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। 77 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

सीएम ने कहा कि यूपी का सबसे बड़ा स्ट्राइक शुभम जायसवाल, कैंट वाराणसी से सपा के प्रत्याशी अमित यादव का

व्यापारिक साझेदार है। सीएम ने आगे कहा कि अमित यादव और मिलिंद यादव के पत्नी के खातों से शुभम के खाते से बैंक ट्रांजेक्शन भी आए हैं। आलोक सिपाही पक्का सपाई है। अखिलेश यादव को गिफ्ट देते उसकी फोटो भी है। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कार्रवाई होगी तो आप लोग (सपा के लोग) ही फातिहा पढ़ने जाएंगे। लेकिन, हम वह भी मौका नहीं देंगे। सीएम योगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को कोर्ट में लड़ा और जीता है।

248 अस्पतालों में कैंसर का इलाज

यूपी में कैंसर का इलाज को लेकर सरकार के स्तर पर प्रयास से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में 248 अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधा

चले तो चिल्लाना मत,
बुलडोजर की भी तैयारी है

कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के सामने कफ सिरप से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, इंतकार कीजिए, बुलडोजर की भी तैयारी है, उस वक्त बस आप लोग चिल्लाना मत

उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें सरकारी क्षेत्र के 26 और निजी क्षेत्र के 222 अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 1,09,450 मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा चुकी है। आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं के तहत बिना जात-धर्म के सभी वर्ग के गरीब मरीजों को केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बिना भेदभाव इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

कार्यवाही शुरू होते ही
सदन में सपा का हंगामा

यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे कोडीन कफ सिरप मामले पर तत्काल चर्चा शुरू कराने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मामला जोरदार तरीके से उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आपकी बातों को हमने सुना है। इस मामले में आगे चर्चा कराएंगे। आपने अपना पक्ष रखा है। आगे सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे पोस्टर पहन और दवा

की बोतल के साथ विधानसभा पहुंचे थे। कार्यवाही के दौरान उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कफ सिरप मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की।



बांग्लादेश हिंसा पर कानपुर में मोहम्मद यूनूस का पुतला दहन

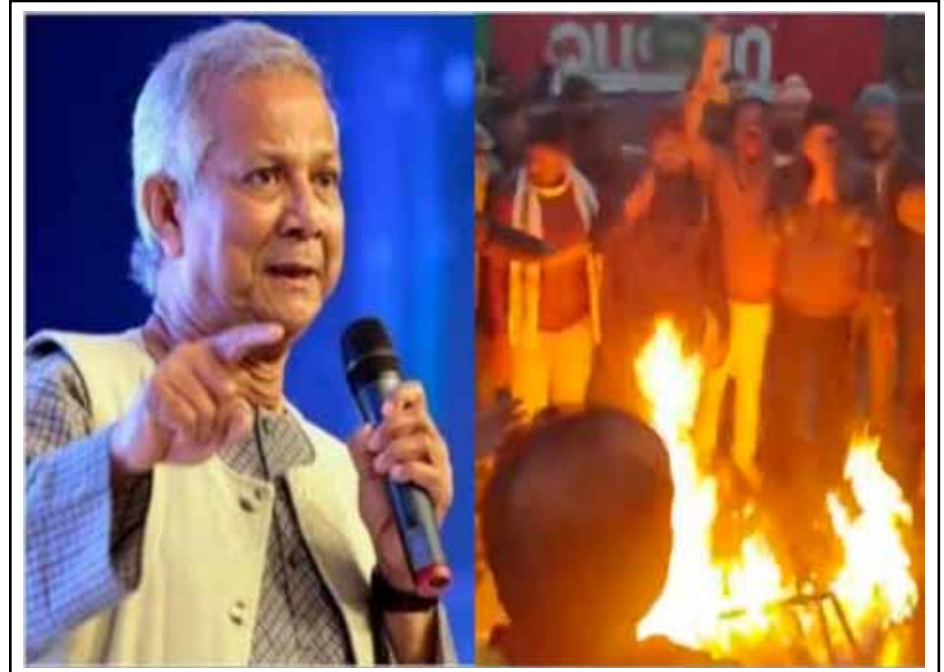
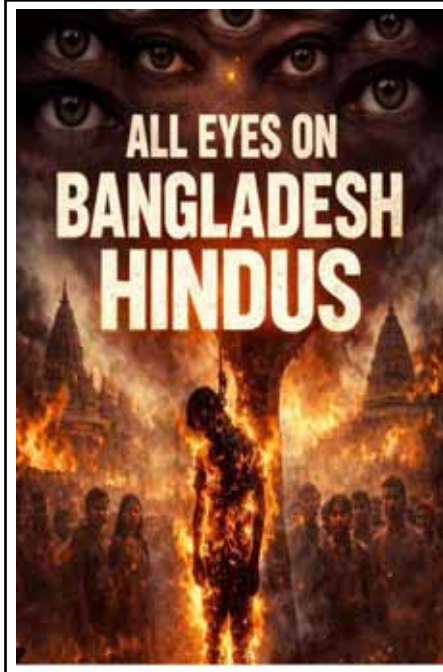
» उल्लंघन और हिंदू समाज पर अत्याचार के विरोध में कड़ा प्रदर्शन

» दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फांसी की मांग, पुलिस रही मौके पर तैनात

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। सिटी के जगईपुरवा में बांग्लादेश के पांचवें मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस का पुतला फूँका गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। यह विरोध उस घटना के बाद तेज हुआ, जब बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हदी की गोली लगने से मौत के बाद मड़की हिंसा में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई।

इनमें एक हिंदू युवक को मारकर पेड़ से लटकाकर जलाने की वारदात भी शामिल बताई जा रही है, जिसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। आई 29 के पार्षद जितेंद्र चौरसिया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ लगातार



अत्याचार और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी रोष के चलते जगईपुरवा चौराहे पर मोहम्मद यूनूस का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया

गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मुख्य सलाहकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और दोषियों को कड़ी सजा देने, यहां तक कि फांसी की मांग की। स्थिति को नियंत्रित रखने

के लिए चकेरी और जाजमऊ पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस विरोध में ज्ञानेश शुक्ला, अनुराग जायसवाल, दिलीप राजपूत, अमन, आदित्य सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

बीच सड़क पर स्कॉर्पियो का आतंक 15 लोगों पर चढ़ाने की कोशिश

ऑटो और तीन बाइकों को रौंदने की कोशिश, एक युवक घायल

» विवाद के बाद लौटकर हमला, अफरा-तफरी के बीच आरोपी फरार

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। जाजमऊ स्थित संजय नगर में रविवार शाम 5-57 बजे स्कॉर्पियो ड्राइवर की दबंगई का चौकाने वाला वीडियो सामने आया है। पुरानी रजिश्त के चलते स्कॉर्पियो चालक ने पहले ऑटो और तीन बाइकों को टक्कर मारी, फिर करीब 15 लोगों को रौंदने की कोशिश की। कार को आगे-पीछे कर बार-बार लोगों की तरफ बढ़ाया गया, जिससे मौके पर मगदड़ मच गई। इस दौरान फुरकान नाम का युवक घायल हो गया। आरोप है कि चालक धमकाते हुए मौके से भाग गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत हॉर्न बजाने से हुई थी, जिसके बाद मामला बढ़ते-बढ़ते हिंसक रूप ले लिया।

पथराव और बंधक बनाने



का आरोप स्थानीय निवासियों के मुताबिक विवाद यहीं नहीं रुका। जाजमऊ की आशियाना कॉलोनी निवासी गुड़िया ने आरोप लगाया कि पहले उनके बेटे को कुछ युवकों ने रोककर पीटा, बाद में 10 से ज्यादा युवकों ने उसे बंधक बना लिया। परिवार के पहुंचने पर पथराव हुआ और इसी दौरान स्कॉर्पियो चालक ने

दोबारा आकर टक्करें मारनी शुरू कीं। चार बार कार पीछे-आगे कर भीड़ को रौंदने की कोशिश की गई, लेकिन लोग किसी तरह भागकर बच निकले। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पुलिस के पास पहुंच चुकी है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला जांच में है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर भारत का तेजी से उभरता...

सांध्यकालीन समाचार पत्र

विज्ञापन एवं सूचनाएं प्रकाशित कराने के लिए सम्पर्क करें:

+91 79851 76100

www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

swarajindianews | swarajinda_top | @swarajindianews

डीएम के निर्देश पर देर रात बड़ा एक्शन

विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 38 चालान, तीन वाहन सीज

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 दिसंबर 2025 की देर रात उप जिलाधिकारी नरवल विवेक कुमार मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक पांडे तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नरवल मोड़ से महाराजपुर थाना क्षेत्र तक व्यापक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सड़क



सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वाहनों की गति पर नियंत्रण, ओवरलोडिंग की जांच, दुर्घटना संभावित स्थलों का आकलन तथा धुंध व ठंड के कारण बनने वाले जोखिम क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण कर भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई की दिशा में पहल की गई।

संयुक्त टीम ने ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरलोड वाहन संचालन जैसे गंभीर यातायात उल्लंघनों पर सख्ती से कार्रवाई की। सभी संदिग्ध चालकों की श्वास परीक्षण यंत्र से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को सीज किया गया और चालान की कार्रवाई की गई।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत

कुल 38 वाहनों के चालान किए गए, तीन वाहनों को सीज किया गया तथा कुल तीन लाख छियानबे हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

कार्रवाई परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रवर्तन के साथ-साथ जन

जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। तहसील नरवल क्षेत्र में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लगातार ऐसे अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है।

सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में

फतेहपुर में बोली राज्यपाल आनंदीबेन

एसआईआर का विरोध न करें घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

फतेहपुर/कानपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि एसआईआर का कार्य लगातार चल रहा है और यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में अवैध रूप से घुसे लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम सरकारें कर रही हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को फतेहपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट वितरित की गई, महिलाओं को पोषण किट दिए गए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।

आंगनबाड़ी व्यवस्था पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं,



लेकिन लंबे समय तक इन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय और अधिकारियों के भवन तो सुविधाओं से युक्त हैं, लेकिन जहां छोटे बच्चे पढ़ते और आते हैं, वहां आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहा। इसी कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की पहल की गई।

राज्यपाल ने बताया कि वर्ष 2019 में पदभार संभालने के बाद आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। बजट की सीमाओं को देखते हुए जनसहयोग के माध्यम से कार्य शुरू किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि अब

तक लगभग 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 22 से 25 हजार रुपये मूल्य के करीब 22 प्रकार के आवश्यक संसाधन पहुंचाए जा चुके हैं।

उन्होंने अपने संबोधन में बेटियों को एचपीवी वैक्सीन दिए जाने के अभियान का भी उल्लेख किया। राज्यपाल ने जिला अधिकारी से आग्रह किया कि जनसहयोग के माध्यम से सरस्वती विद्या मंदिर और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी पात्र छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर यह टीका लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि पुलिस कॉलोनियों का सर्वे कराकर वहां रहने वाली 9 से 15 वर्ष आयु की बच्चियों की सूची तैयार की जाए और उनका टीकाकरण कराया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मी चौबीस घंटे जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसलिए उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी समाज और सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाना और उन्हें स्वस्थ भविष्य देना है।

मकनपुर बसंत मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, प्रशासन अलर्ट

एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो। बिल्हौर(कानपुर)। सूफी संत हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदर की दरगाह पर आयोजित होने

वाला ऐतिहासिक मेला इस बार आगामी तारीख 17 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित आमद को देखते हुए

प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रविवार को एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित ने तहसीलदार अनुभव



» 17 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा मेला।

चंद्रा और बीडीओ नेम चंद्र के साथ मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने सबसे पहले मेला तहसील परिसर का जायजा लिया। इसके बाद मेला कमेटी के सदस्यों के साथ प्राचीन दरगाह हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदर पहुंचे। दरगाह परिसर में परंपरागत रीति-रिवाजों के तहत पगड़ी बांधकर अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने दरगाह पर माथा टेका। निरीक्षण के दौरान मेला तहसील भवन,कोतवाली भवन, कंट्रोल रूम, मुसाफिरखाना, अधिकारी आवास सहित अन्य प्रमुख स्थलों की व्यवस्थाओं को परखा गया।

एसडीएम ने साफ शब्दों में कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्राम प्रधान को निर्देश दिए कि मेला आरंभ होने से पहले पूरे क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर अलग से कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि बसंत मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान इंस्पेक्टर जनार्दन यादव, क्षेत्रीय लेखपाल सुनील चौधरी, ग्राम प्रधान मजाहिर हुसैन जाफरी, भाजपा नेता नन्द लालपाल,दीपक समेत कई लोग मौजूद रहे।

कार्यालय अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी मेला मकनपुर बिल्हौर कानपुर नगर

पत्रांक- 01/खजांची/2026

दिनांक: 22 दिसम्बर, 2025

अल्पकालीन निविदा सूचना बसंत मेला मकनपुर वर्ष 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बसंत मेला मकनपुर वर्ष 2026 दिनांक 17.01.2026 से 03.02.2026 तक गतवर्षों की भांति आयोजित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में नीचे अंकित तालिका के अनुसार विभिन्न कार्यों की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 25.12.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक तहसील बिल्हौर में आमंत्रित की जा रही है। प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी मेला मकनपुर बिल्हौर की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा फार्म दिनांक 25.12.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित मूल्य 500 /- रू० जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धरोहर राशि	कार्य की अवधि
1.	पशु रजिस्ट्रेशन	50,000 /-	17.01.2026 से 03.02.2026 तक
2.	बैरियर टोल टैक्स	10,000 /-	17.01.2026 से 03.02.2026 तक
3.	वाहन पार्किंग	10,000 /-	17.01.2026 से 03.02.2026 तक
4.	टेन्ट व फर्नीचर	10,000 /-	17.01.2026 से 03.02.2026 तक
5.	विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में जनरेटर द्वारा एवं साज सज्जा।	50,000 /-	17.01.2026 से 03.02.2026 तक

निविदा की मुख्य शर्तें-

- निविदा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोले जायेंगे।
- धरोहर राशि नगद जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- स्वीकृत निविदादाताओं को तीन दिन के अन्दर सचिव, मेला मकनपुर से अनुबन्ध करना होगा।
- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी बिल्हौर को होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा में बोली की धनराशि का स्पष्ट अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
- निविदादाताओं को अपने मूल निवास के तहसीलदार से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि किसी भी शर्तें का उल्लंघन होता तो निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

**अध्यक्ष मेला मकनपुर / उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।**

समाचार पत्र वितरक पर कार सवारों का हमला



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे बाईपास पर गौरी अंडरपास के पास रविवार तड़के कार सवार बदमाशों ने एक समाचार पत्र वितरक पर हमला कर दिया। रास्ता पूछने के बहाने रोके जाने के बाद हमलावरों ने मारपीट की और साइकिल में टंगा थैला लेकर फरार हो गए।

शाहमपुरकोट गांव निवासी कुलदीप यादव प्रतिदिन भोर में साइकिल से बिल्हौर आकर समाचार पत्र वितरण करते हैं। रविवार सुबह करीब छह बजे गौरी गांव के सामने अंडरपास के पास एक लाल रंग की मारुति सुजुकी कार खड़ी दिखी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वही कार पीछे से आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने बिल्हौर जाने का रास्ता पूछा। इसी दौरान पिछली सीट से उतरे दो युवकों ने अचानक कुलदीप पर पीछे से हमला कर दिया। अनहोनी की आशंका पर वह साइकिल छोड़कर भागे, गिरने से उन्हें मामूली चोटें आईं।

बदमाश साइकिल में टंगा थैला जिसमें डायरी व पेन थे लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर बदमाश हाईवे किनारे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर कुलदीप थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर सदिग्ध कार की तलाश तेज कर दी है।

सम्पादकीय

दीर्घकालिक शांति की जाए सुनिश्चित

लंबे समय तक अशांत रहे मणिपुर के मुद्दे पर अकसर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। अब वह प्रतीक्षित यात्रा हकीकत बनी है। कहा जा सकता है कि संघर्षरत राज्य की जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर करने का यह सार्थक प्रयास जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने का संकल्प जताया है। लेकिन मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति सरकार के संकल्प की परीक्षा लेगी। हालांकि, लगभग ढाई साल पहले भड़की जातीय हिंसा हाल के महीनों में, खासकर फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कम हो गई है। लेकिन भविष्य में हिंसा की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है।

ऐसी दशा में इस संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार को सामान्य स्थिति की बहाली और दीर्घकालिक शांति स्थापना के लिये हर संभव प्रयास करने चाहिए। दरअसल, राज्य में स्थायी शांति के मार्ग में जो एक सबसे बड़ी बाधा है, वह है पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय और घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच लगातार कम होता विश्वास। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि दोनों समुदायों की आकांक्षाओं में संतुलन बनाए। ताकि दोनों समुदायों की चिंता और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके। विगत में मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग करते रहे हैं। यह एक ऐसा विवादस्पद मुद्दा था, जिसने कुकी-जो समुदाय के लोगों में असुरक्षा व अशांति पैदा कर दी। जिसे दूर किए जाने की सख्त जरूरत है।

दरअसल, हाल के हिंसक संघर्ष ने

राज्य में मतभेदों को मनभेद में बदल दिया है। कुकी-जो विधायकों के एक समूह, जिसमें भाजपा के भी सात विधायक शामिल हैं, ने कहा है कि 'दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं, लेकिन फिर कभी एक छत के नीचे नहीं।' उनकी मांग रही है कि गैर-मैतेई समुदायों के लिये अलग विधायिका सहित अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। यह सोच दोनों समुदायों के बीच गहरे मतभेद को उजागर करती है, जिसने मणिपुर को गहरी क्षति पहुंचाया है। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अभी डेढ़ साल बाकी है। राज्य में हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है ताकि विधानसभा चुनाव में देरी न हो।

केंद्र सरकार को विधानसभा को लंबे समय तक निलंबित रखने के फायदे और नुकसान का भी आकलन करना होगा। लेकिन फिलहाल, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर देने की जरूरत है। उससे भी महत्वपूर्ण, राज्य में सक्रिय चरमपंथी समूहों के लोगों को हथियार डालने के लिये प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

विकास परियोजनाओं पर काम जल्दी शुरू करने तथा उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने से भी मणिपुर के लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसे तमाम प्रयास मणिपुर के आहत लोगों की विश्वास बहाली में मददगार साबित हो सकते हैं। निस्संदेह, इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

वैचारिक मंच

पड़ोस के घटनाक्रम पर रहे पैनी नज़र

पुष्कर जैन

नेपाल में जेन जी की हालिया हिंसक क्रांति अचभित करने वाली थी। नेतृत्व से युवा तंग आ चुके थे। बहरहाल, नयी सरकार बनने तक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बतौर अंतरिम प्रधानमंत्री शपथ दिलाई गयी। इससे पूर्व दो अन्य पड़ोसी देशों के लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कब्जाने के विरुद्ध इच्छाशक्ति दिखाई। भारत के लिए सबक है कि दक्षिण एशिया को ध्यान के केंद्र में रखे पिछले हफ्ते की शुरुआत में नेपाल में क्रांति इतनी अचानक, इतनी त्वरित और इतनी नाटकीय थी कि भारत तक अचभित रह गया। जब पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की सशस्त्र पुलिस ने युवा छात्र प्रदर्शनकारियों पर, जिनमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे भी शामिल थे, निर्ममता से गोलियां चलाई, तो भारतीय अधिकारियों को तुरंत अहसास हो गया कि पुरानी व्यवस्था ढह रही है। वे तो 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओली की भारत यात्रा की तैयारियां कर रहे थे। वे स्तब्ध थे कि इससे एकदम पहले ही घटनाओं ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया।

भारत-नेपाल संबंधों की खासियत यह है कि यह इतना घनिष्ठ, इतना गहरा और अटूट है कि भारत के रिश्ते किसी अन्य देश के साथ इस जैसे नहीं हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने कुछ साल पहले तराई और भारत के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के बीच इस 'रोटी-बेटी' के रिश्ते को दिल्ली के अभिजात वर्ग को बताकर चौंका दिया था, लेकिन यह मुहावरा नेपाल और भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी उतना ही सच है। नेपाल के अभिजात वर्ग और सर्वहारा वर्ग- 'बाहुन' और 'छेत्री', पहाड़ों के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, और निचले एवं मैदानी इलाकों के अन्य जातियों के लोग - भारत में विवाह करते आए हैं या बसे हैं और काम करते हैं और भारतीय भी इसी तरह से वहां रहते-काम करते हैं। रिश्तेदारी के बंधन पीढ़ियों को नया रूप देते रहे। अगर आप पटना से जनकपुर तक



गाड़ी से जाते हैं, तो खुली सीमा पार करते समय कोई भी आपकी तरफ दुबारा गौर तक नहीं करता।

आप दलील दे सकते हैं कि यह बात तो भारत के हर पड़ोसी के लिए भी सच है, कि जातीयता, धर्म और संस्कृति-भूगोल एवं संप्रभुता- दोनों से, परे होती हैं। निश्चित रूप से, यह उन तीन देशों के लिए विशेष रूप से सच है जिनके लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कब्जाने के विरुद्ध अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है- 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब नेपाल। इन सभी क्रांतियों में छोटे-बड़े अंतरों के बावजूद, मौलिक समानता अभेद है। लोग इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि वे उस नेतृत्व से तंग आ गए, जिन्हें उन्होंने वोट डालकर चुना था लेकिन वे उन्हें ही गले में फंदा डालकर मवेशियों की तरह हांकेने लगे (काठमांडू में चीजें तेजी से बदलीं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा चुकी है और संसद भंग कर दी गई है। तथापि, सत्ता के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे संकेत हैं कि नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल-जिन्हें भारत-नेपाल विशेष संबंधों के चलते पिछले दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना में 'ब्रदर जनरल' का मानद पद प्रदान किया गया था-अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और संभवतः राजशाही समर्थक राजनेताओं के पक्ष में झुकाव रखते हैं।

श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग से सधेंगे आर्थिक लक्ष्य

नये परिदृश्य की चुनौती

शुभम चौधरी

यदि हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान कर सकें तो औसत आयु और शारीरिक विकास में और सुधार संभव है। भारत में आगामी जनगणना की घोषणा कर दी गई है, जिसमें जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। इस जातिगत जनगणना का उद्देश्य विपत वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उनके कल्याण के लिए प्रभावी नीतियां बनाना है। हालांकि, यदि इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण किया गया, तो इसके सामाजिक लाभ की बजाय केवल राजनीतिक नाशों और वादों का शोर सुनाई देगा, जिससे विपत वर्गों को वास्तविक लाभ मिलने की बजाय केवल निराशा ही हाथ लगेगी।

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण जन्म और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पहले जहां कई शिशु उचित चिकित्सा के अभाव में पांच वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते थे, अब उनकी संख्या आधी रह गई है। साथ ही, औसत आयु बढ़कर अब 72 वर्ष हो गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यदि हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान कर सकें तो औसत आयु और शारीरिक विकास में और सुधार संभव है। भारत में लोगों को रियायती राशन तो मिल रहा है, परंतु उन्हें गुणवत्ता युक्त जीवन और रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही है। इसका सीधा असर बच्चों के पोषण पर पड़ रहा है। नतीजतन, देश में कुपोषण की समस्या बनी हुई है, जिससे कुछ बच्चे छोटे कद के पैदा हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोटापा भी स्वास्थ्य के लिए

चुनौती है। हालिया आंकड़ों की वर्तमान में प्रजनन दर 1.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए न्यूनतम दर 2.1 प्रतिशत होनी चाहिए। इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर अभी भी 2.1 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह घटकर 1.6 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में किशोर और युवा जनसंख्या की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम होती जाएगी, और वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा। इसके विपरीत, ग्रामीण भारत में यह असंतुलन अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा। इस बदलाव का सामाजिक और भौतिक ढांचे पर भी असर दिखने लगा है। शहरी क्षेत्रों में अब वृद्धजनों के अनुकूल रहन-सहन की मांग बढ़ रही है। इसलिए

नियोजित प्लेट, वृद्धाश्रम, और ऐसी बस्तियों का निर्माण बढ़ रहा है जहां बुजुर्ग सुरक्षित और सहज जीवन व्यतीत कर सकें। यदि यह गिरती हुई प्रजनन दर बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में भारत की कार्यशील जनसंख्या में कमी आ सकती है। तब भारत को एक युवा देश कह पाना कठिन होगा। जिस प्रकार हम जापान और चीन के बारे में कहते हैं कि वहां वृद्धजन अधिक और युवाजन घटते जा रहे हैं, भारत के शहरी क्षेत्रों में भी यह स्थिति उभर सकती है, खासकर तब जब परिवार नियोजन पर अत्यधिक बल दिया जाए। साथ ही जनसंख्या परिवर्तन का राजनीतिक उपयोग भी देखा जा रहा है। कुछ वर्गों द्वारा इन आंकड़ों को अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे जनसंख्या नीतियों का संतुलन बिगड़ने की आशंका

है। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु से यह स्वर उभरा है कि वहां के लोगों ने समय रहते परिवार नियोजन अपनाया, जबकि उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश-बिहार इस दिशा में अपेक्षाकृत पीछे रह गए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में जनसंख्या वितरण असंतुलित हो गया है। अब जब जनसंख्या के आधार पर संसदीय प्रतिनिधित्व तय होता है, तो दक्षिण भारत को आशंका है कि कम जनसंख्या के कारण उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि आधुनिकता के दावों के बावजूद भारत में महिलाओं को रोजगार और उन्नति के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। केवल सीमित प्रतिशत में महिलाएं ही औपचारिक कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि शेष घरलू या खेतों में कार्यरत हैं, जिनका श्रम अवसर अनदेखा रह जाता है।

आईआईटी कानपुर को देना ही होगा एनएचआरसी को जवाब !

» एनएचआरसी के सामने आईआईटी के दावे पर याचिकाकर्ता पंकज सिंह ने दागे सवाल तो एनएचआरसी ने डीएसटी सचिव और आईआईटी कानपुर के निदेशक से माँगा जवाब

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर /नई दिल्ली। आईआईटी कानपुर कैम्पस में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर कल्याणपुर आवास विकास केशवपुरम निवासी पेशे से इंजीनियर पंकज कुमार सिंह ने एनएचआरसी में याचिका दाखिल की थी। पिछले वर्ष 30 दिनों के भीतर तीन छात्रों की आत्महत्या की घटना से अहत पंकज ने विगत 19 वर्षों में घटित समस्त घटनाओं के पीड़ित परिजनों को न्याय के लिए जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। एनएचआरसी ने केंद्र के मानवसंसाधन मंत्रालय शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सहित आईआईटी कानपुर के निदेशक को तलब करते हुए नोटिस जारी किये थे। आईआईटी ने विगत 16 मई 2025 की सुनवाई दौरान 18 बिंदुओं पर अपने जवाब पेश किये थे जिसमें आईआईटी द्वारा लगातार छात्रों की मॉनिटरिंग और काउंसलिंग कर आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों और प्रयासों का उल्लेख किया था।

सोमवार 15 दिसंबर 2025 को एनएचआरसी में हुई केस की सुनवाई के दौरान आईआईटी द्वारा एनएचआरसी के समक्ष 18 बिंदुओं के जवाब पर याचिकाकर्ता पंकज कुमार सिंह ने आपत्ति जताते हुए अपनी टिप्पणियों के

एनएचआरसी ने आईआईटी को 22 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है



साथ सवाल किये। पंकज ने कहा कि आरटीआई से मांगे जवाब में आत्महत्या के मामलों की जांच व निष्कर्ष पर आईआईटी रिकॉर्ड न बात कही वहीं कई सवालों से किनारा करते हुए जवाब नहीं दिया। पंकज ने एनएचआरसी कोर्ट से अनुरोध किया और कहा आईआईटी द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई की रिपोर्ट को अधूरी और एकतरफा माना जाए क्योंकि उसमें छात्र छात्राओं की आत्महत्या के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने संस्थान में हर आत्महत्या मामले का कॉज एनालिसिस रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि इसकी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा घटना को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर जाँच की जाती है, ऐसे में सभी आत्महत्या की घटनाओं पर पुलिस ने अपनी जाँच में तथा मृतक के पोस्टमार्टम और पंचनामा में क्या पाया ? और मुकदमा की स्थिति क्या है इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने किये जाने की मांग की है। एनएचआरसी ने याचिकाकर्ता पंकज कुमार सिंह की आपत्तियों पर गौर करते हुए जिम्मेदारों

तलब किया। आयोग की ओर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ ब्रजवीर सिंह ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक सहित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को चार सप्ताह में पंकज की आपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

आईआईटी के दावे पर पंकज ने दागे सवाल

याचिकाकर्ता पंकज कुमार सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा आईआईटी के दावे मुख्यतः नीतिगत व घोषणात्मक हैं, जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता।

उन्होंने टिप्पणियां दाखिल करते हुए कहा कि आईआईटी की योजनात्मक पहल बाद आत्महत्या की घटनाएं रुकीं? छात्रों के तनाव, असफलता, या टर्मिनेशन के डर को कम किया जा सका? इन सभी सेवाओं का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या और उनका फीडबैक क्या रहा? इसका जवाब में आईआईटी की चुप्पी

दिखी। गत 19 वर्षों में हुई आत्महत्याओं की आंतरिक जांच रिपोर्ट कहाँ है? किसी भी मामले में संस्थान के किसी अधिकारी या शिक्षक की भूमिका की समीक्षा हुई?

आत्महत्या की घटनाओं पर पुलिस ने अपनी जाँच में तथा मृतक के पोस्टमार्टम और पंचनामा में क्या पाया ? और मुकदमा की स्थिति क्या है? आईआईटी का दावा है कि वह छात्रों से फीडबैक लेता है तो क्या यह डेटा एनएचआरसी या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है? पंकज ने कई सवालों के घेरे में लेते हुए कहा सारी व्यवस्थाएँ केवल कागजी दिखावे की हैं, उनका जमीनी असर नगण्य है।

आईआईटी के दावे की पोल खोलती छात्र धीरज सैनी की मौत

एनएचआरसी में आईआईटी के दावों की पोल तब खुल गई जब छात्र धीरज सैनी का शव तीन दिनों तक फंदे पर लटका रहा और किसी को घटना की खबर न लग सकी। याचिकाकर्ता पंकज कुमार सिंह ने एनएचआरसी को इस घटना की

रिपोर्ट भेज आईआईटी को सवालों के साथ घेर लिया।

आईआईटी कानपुर में लगातार छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आईआईटी लगातार आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के खोखले दावे करता रहा गौरतलब है 20 दिसंबर 2023 को उड़ीसा निवासी बायो इंजीनियरिंग की डॉ पल्लवी चिल्का ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी।

10 जनवरी 2024 को एयरोस्पेस के छात्र विकास मीणा की मौत की खबर प्रकाश में आई थी।

18 जनवरी 2024 केमिकल इंजीनियरिंग की 29 वर्षीय शोधार्थी प्रियंका जायसवाल रस्सी के फंदे पर पंखे से लटकी पाई गई थी। इसी तरह 10 अक्टूबर 2024 को शोधार्थी प्रगति, 10 फरवरी 2025 को सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक चौधरी और 01 अक्टूबर 2025 को बीटेक फाइनल ईयर छात्र धीरज सैनी की मौत सहित ये कुल दो वर्षों में हुई आत्महत्या की घटनाएं हैं।

नवाबगंज में 21वां वैभव महालक्ष्मी यज्ञ का हुआ शुभारंभ

वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ सूर्य विहार से नवाबगंज स्थित शक्ति पीठ तक निकाली गई कलश यात्रा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। विगत वर्षों की भांति मां आनंदी देवी शक्ति पीठ, सुखरू पुरवा नवाबगंज में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के वातावरण में कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ सूर्य विहार से नवाबगंज स्थित शक्ति पीठ तक निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी के साथ 21वां विशाल वैभव महा लक्ष्मी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। महा लक्ष्मी यज्ञ का पूजन आचार्य

घनश्याम मिश्रा द्वारा विधि-विधान से संपन्न कराया गया। अन्य आचार्यों के साथ मंत्र मंथन के दौरान अग्नि देव का प्राकट्य हुआ, जिसके पश्चात भक्तों ने यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कीं। पूरे क्षेत्र में मंत्रोच्चार और भक्तिमय वातावरण बना रहा। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चलती रहीं, जबकि श्रद्धालु जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आए। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति से माहौल उल्लासपूर्ण हो गया। महा लक्ष्मी यज्ञ में अमन मिश्रा, अंशुल मिश्रा, आनंदी



गोपी, गोविंद, हरिओम, अनिल, शशिकांत सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई है।

ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, सतर्क रहें सुरक्षित रहें



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनहित में विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी ने बताया कि शीतलहर के दौरान सतर्कता और सावधानी बरतने से जनहानि और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय रेडियो, दैनिक समाचार पत्र, टीवी और मोबाइल के माध्यम से मौसम की ताजा जानकारी नियमित रूप से लेते रहें। कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल का चूल्हा, हीटर या ब्लोवर का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें और कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखें, ताकि जहरीली गैस या धुआं एकत्र न हो। शरीर को सूखा रखना जरूरी है और गीले कपड़े तुरंत बदल लेने चाहिए। अत्यधिक ठंड के दिनों में यदि घर में अलाव की व्यवस्था न हो तो प्रशासन द्वारा बनाए गए सामुदायिक केंद्रों और आश्रय स्थलों पर जाएं, जहां अलाव की सुविधा उपलब्ध है।

एडवाइजरी में बताया गया है कि कई परतों वाले गर्म ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी और मफलर शीतलहर के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। ऊनी कपड़ों की कमी होने पर दो-तीन कपड़े एक के ऊपर एक पहनकर भी ठंड से बचाव किया जा सकता है। अत्यधिक ठंड और कोहरे के दौरान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को यथासंभव घर के भीतर ही रखें। शरीर की ऊष्मा बनाए रखने के लिए पोषक आहार और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें तथा धूप निकलने पर उसका लाभ अवश्य लें। जिलाधिकारी ने हाइपोथर्मिया के लक्षणों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि शरीर का असामान्य तापमान, भ्रम या स्मृति हानि, बेहोशी, अत्यधिक ठिठुरन, सुस्ती, थकान या तुतलाहट जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। इसी तरह शीतदंश की स्थिति में हाथ-पैर की उंगलियों, कान या नाक का सुन्न पड़ना अथवा सफेद या पीले रंग के दाग उभरने पर भी तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है।

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि आसपास अकेले रहने वाले पड़ोसियों, विशेषकर बुजुर्गों की जानकारी रखें और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ठंड के मौसम में पालतू पशुओं और पक्षियों के बाड़ों को ऊष्मा रोधी बनाएं, खिड़की-दरवाजे ढककर रखें, लेकिन वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त स्थान खुला छोड़ें। सिगड़ी, अलाव या अंगीठी सोते समय बुझाकर ही सोएं और इन्हें बंद स्थानों पर जलाने से बचें, ताकि आगजनी की घटनाएं न हों। यदि कोई निराश्रित, असहाय, विकलांग, बीमार या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ठंड से प्रभावित दिखाई दे तो क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से उन्हें निःशुल्क कंबल दिलाने में सहयोग करें।

शीतलहर से पहले और उसके दौरान अपनाए जाने वाले उपायों को भी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है। नागरिकों से कहा गया है कि मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें, पर्याप्त सर्दियों के कपड़े पहनें, आपातकालीन आवश्यक सामग्री पहले से तैयार रखें और ठंड से जुड़ी बीमारियों के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शीतलहर के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, ढीले और हवा रोकने वाले कपड़ों की कई परतें पहनें, सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को अच्छी तरह ढके, दरताने, टोपी और मफलर का उपयोग करें, विटामिन-सी युक्त फल-सब्जियां खाएं और नियमित रूप से गर्म तरल पेय का सेवन करते रहें।



दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में जरूरतमंद श्रमिकों को कंबल वितरण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कड़ाके की ठंड के बीच नेककाज चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से रविवार को दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेवा कार्य के तहत कुल 501 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज अग्रवाल ने किया। उन्होंने सोसाइटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना समाज के प्रति महत्वपूर्ण दायित्व है, जिससे मानवता मजबूत होती है। सोसाइटी के अध्यक्ष सुनील मेहता और उपाध्यक्ष अखिलेश गर्ग ने बताया कि नेककाज चैरिटेबल सोसाइटी वर्ष 2015 से कानपुर क्षेत्र में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर सक्रिय है। संस्था द्वारा समय-समय पर कंबल वितरण, स्वास्थ्य शिविर और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।

कार्यक्रम में अरुण मिश्रा, धर्मेन्द्र अवस्थी, आलोक त्रिपाठी, एस.के. सिंह, एस.एन. सिंह, प्रमोद कुमार, के.के. सिंह, राम कुमार यादव सहित सोसाइटी के अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कंबल पाकर श्रमिकों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ नजर आई।

अयोध्या में विकास योजनाएं फाइलों में दौड़ रही, ज़मीन पर नहीं

डबल इंजन की रफतार पर प्राधिकरण का ब्रेक

- » विकास प्राधिकरण की सुस्ती से करोड़ों की परियोजना पर फिर रहा पानी
- » दीपोत्सव की हृदय स्थली राम की पैड़ी के सामने बना सफेद हाथी
- » लता चौक से पुराने सरयू पुल तक 300 मीटर का चौड़ीकरण बना विकास की असलियत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। देश और प्रदेश की सबसे चर्चित धार्मिक-पर्यटन नगरी अयोध्या में विकास को लेकर मोदीइयों की डबल इंजन सरकार हर महीने समीक्षा, निर्देश और डेलाइन जारी करती है। मंचों से विकास की रफतार का दावा होता है, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की सुस्ती ने करोड़ों की विकास

परियोजनाओं को ऐसे जकड़ रखा है कि न आगे बढ़ पा रही हैं, न पीछे लौट पा रही हैं। राम की पैड़ी के सामने 'विकास' का सफेद हाथी दीपोत्सव की हृदय स्थली राम की पैड़ी के ठीक सामने करोड़ों की लागत से बना कॉम्प्लेक्स आज विकास नहीं, बल्कि प्रशासनिक जड़ता का स्मारक बन चुका है। दर्जनों दुकानें तैयार हैं, लेकिन उनके शटर वर्षों से बंद पड़े हैं। न सीवर कनेक्शन, न बिजली, न पानी, न नाली-कागजों में सब कुछ पूरा, हकीकत में सब कुछ अधूरा।

लता चौक से पुराने सरयू पुल तक महज़ 300 मीटर का सड़क चौड़ीकरण आज पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस छोटे से हिस्से में 14 दुकानों का विस्थापन अब तक नहीं हो पाया है। शौचालय तोड़ दिया गया, लेकिन पुनर्निर्माण की फाइल आज भी रास्ता ढूँढ़ रही है। नतीजा आधा-अधूरा चौड़ीकरण, बदहाल यातायात और रोज़ जाम से जूझती रामनगरी। अधिकारी बदल गए, काम ठहर गया विकास प्राधिकरण के एक जिम्मेदार अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया अगर पहले वाले अधिकारी (सत्येंद्र सिंह) होते, तो ये चौड़ीकरण कब का पूरा हो चुका



होता। मौजूदा सचिव के रिटायरमेंट में सिर्फ तीन महीने बचे हैं, दिलचस्पी नहीं है, इसलिए परियोजना लटकी हुई है। यानी विकास अब नीति से नहीं, व्यक्ति की रुचि से तय हो रहा है। कॉम्प्लेक्स और चौड़ीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन दुकानों के सीवर, बिजली और पानी की व्यवस्था आज भी जस की तस है। सवाल यह नहीं कि पैसा कहां गया, सवाल यह है कि काम क्यों नहीं हुआ? पीडब्ल्यूडी तैयार, प्राधिकरण ठहरालोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एस.पी. भारतीय साफ

कहते हैं हमारी तरफ से चौड़ीकरण का काम 99 प्रतिशत पूरा है। विकास प्राधिकरण दुकानें विस्थापित कर दे, तो हम 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। हमने कई बार संपर्क किया, लेकिन विलंब का कारण नहीं बताया गया। यानी एक विभाग तैयार खड़ा है, दूसरा विभाग मौन साधे बैठा है। सवाल जो सिस्टम से टकराते हैं वह यह है कि क्या अयोध्या में विकास योजनाएं रिटायरमेंट कैलेंडर देखकर चल रही हैं? क्या डबल इंजन सरकार की डेलाइनों विकास प्राधिकरण के लिए सिर्फ औपचारिकता हैं? जनता की मांग है कि अयोध्या जैसे अंतरराष्ट्रीय पहचान वाले तीर्थ में विकास कार्यों की यह हालत सिर्फ लापरवाही नहीं, जवाबदेही का संकट है। जरूरत है समयबद्ध विस्थापन जवाबदेह अधिकारियों की पहचान और परियोजनाओं की सार्वजनिक मॉनिटरिंग वरना रामनगरी में विकास के नाम पर कॉम्प्लेक्स सफेद हाथी बनते रहेंगे और सड़कें सवाल पूछती रहेंगी।



समाजवादी पार्टी की एसआईआर बैठक के दौरान भिड़े सपाई

» मीटिंग में पहुंचा आपसी विवाद, हाथापाई के बाद खत्म हुई बैठक



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रविवार को रसूलाबाद स्थित पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी की एसआईआर बैठक होनी थी। जहां बैठक चल रही थी। इसी दौरान मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते हंगामा कार्यालय की सीढ़ियों की ओर पहुंचा तो चौराहा पर निकलते लोगों का जमावड़ा हो गया। बड़े नेताओं ने किसी तरह मामला सुलझाया और हंगामा के साथ मीटिंग खत्म

हो गई।

सोमवार को रसूलाबाद कस्बे के मुख्य चौराहा पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में एसआईआर को लेकर बैठक चल रही थी।

जिसमें पूर्व सांसद राजाराम पाल जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। वाद-विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐलान करके चौराहा पर बुलाया गया और देख लेने

की बात कही गई। जिसके चलते मीटिंग के दौरान ही दो पक्षों में हाथापाई शुरू हुई तो कुछ कुर्सियां भी टूट गईं। रसूलाबाद कस्बे के एक युवा सपा नेता ने बताया कि उनको सपा के जिला प्रभारी द्वारा फोन से गाली गलौज के साथ अपमानित किया गया। जबकि जिला प्रभारी ने आरोप लगाया कि सपा नेता द्वारा उनकी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई जिसके चलते विवाद उपजा व हंगामे के चलते मीटिंग समाप्त हो गई।

बेटे ने किया धर्म परिवर्तन संपत्ति के लिए पिता की जान का बना दुश्मन

पीड़ित ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार, धर्म परिवर्तन कर चुके पुत्र को संपत्ति से किया बेदखल

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर रामहार गांव में धर्म परिवर्तन के बाद बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का वृद्ध पिता ने फैसला किया तो वही बेटा वृद्ध पिता की जान का दुश्मन बन गया। पीड़ित पिता ने उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम अलीपुर रामहार निवासी 85 वर्षीय वृद्ध क्षमा दास ने अपने एक बेटे बेटे द्वारा वर्षों पूर्व धर्म परिवर्तन किए जाने और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन न करने के चलते उसे संपत्ति से बेदखल किए जाने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। पीड़ित क्षमा दास ने बताया कि उनके चार पुत्र वेदप्रकाश, प्रेमप्रकाश उर्फ सरदार आजाद सिंह, सत्यप्रकाश व जयप्रकाश हैं। आरोप है कि प्रेमप्रकाश उर्फ सरदार आजाद सिंह ने करीब 35 वर्ष पूर्व धर्म परिवर्तन कर लिया था, जबकि छोटा बेटा जयप्रकाश लगभग 30 वर्षों



से घर से बाहर रह रहा है और परिवार से कोई संपर्क नहीं रखता वृद्ध पिता का कहना है कि वर्तमान में उनकी देखभाल बड़े बेटे वेदप्रकाश व सत्यप्रकाश तथा उनके परिजन कर रहे हैं। वहीं प्रेमप्रकाश उर्फ सरदार आजाद सिंह और जयप्रकाश ने कभी भी उनकी सेवा या देखभाल नहीं की इसी को लेकर क्षमा दास ने दोनों पुत्रों को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल किए जाने की अनुमति देने की मांग करते हुए उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी।

अकबरपुर में संत गाडगे महाराज का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 नेहरू नगर में शनिवार को स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज का 69वां परिनिर्वाण दिवस सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, स्वच्छता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर अखिल भारतीय संत गाडगे धोबी महासभा के जिला अध्यक्ष बबलू भारती ने कहा कि बीसवीं सदी के समाज सुधार आंदोलन में संत गाडगे महाराज का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और मानवता को केंद्र में रखकर समाज में फैली छुआछूत, जाति प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरण किया। दबे-कुचले समाज को नई दिशा देने वाले राष्ट्र संत गाडगे बाबा ने अपने जीवन से सेवा और समर्पण की

मिसाल पेश की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता मिशन संत गाडगे महाराज की प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहा है। संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जनपद की अंजनगांव सुरजी तहसील के शेगांव गांव में हुआ था। उन्होंने सदैव स्वच्छता को प्राथमिकता दी और धर्मशालाओं, विद्यालयों तथा शिक्षा के प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए। कार्यक्रम में सभासद बबलू भारती, सरदार प्रमोद सिंह केसावत, सभासद आदेश यादव, सभासद शिव सिंह नायक, सभासद रामपाल नायक, राम लखन दिवाकर, शिव शंकर कुशवाहा, जसवंत सिंह, मुस्लिम अली, विष्णु प्रकाश गुप्ता, सुरजन लाल दिवाकर, किशन लाल दिवाकर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने संत गाडगे महाराज के आदर्शों को अपनाने और स्वच्छ समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

सरवनखेड़ा पीएचसी प्रभारी के रवैये से त्रस्त आशा बहुएं

» मानसिक उत्पीड़न और मानदेय न मिलने का आरोप, स्थानांतरण तक कार्य बहिष्कार का एलान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (माती)। सरवनखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में तेनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश यादव के खिलाफ आशा एवं संगिनी बहुओं का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने की कगार पर है। प्रभारी पर मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा के प्रयोग, चार माह से मानदेय रोके जाने और धमकी भरे पत्र जारी कर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए आशा बहुओं ने स्थानांतरण तक कार्य बहिष्कार का एलान किया है। बताया गया कि सरवनखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशा एवं संगिनी बहुओं ने सामूहिक रूप से जिला अध्यक्ष रेणुका सचान को शिकायती पत्र सौंपा है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आए दिन मर्यादा को तार-तार करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटी से हटाने, मानदेय रुकवाने और सेवा समाप्त करने की धमकी देते हुए लिखित पत्र जारी कर भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे आशा बहुएं मानसिक



दबाव में कार्य करने को मजबूर हैं। शिकायत करने वाली आशा बहुओं में सुनीता देवी, गंगा देवी, मंजू देवी, पूनम देवी, आशा देवी, रेखा देवी, कुसुम देवी, सीमा देवी, शांति देवी, सविता देवी, सरोज देवी, उर्मिला देवी, रानी देवी, पुष्पा देवी, मीना देवी, विमला देवी, रश्मि देवी, गीता देवी, सुलेखा, शकुंतला, सुशीला देवी सहित बड़ी संख्या में आशा एवं संगिनी बहुएं शामिल हैं। सभी ने एक स्वर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई है। आशा बहुओं ने पत्र में बताया कि बीते चार महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार की जिम्मेदारी निभा रही आशा बहुएं लगातार वेतन न मिलने और मानसिक उत्पीड़न के कारण भारी तनाव से गुजर रही हैं। शिकायत

पत्र में एक अत्यंत चिंताजनक तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि इसी तरह के मानसिक दबाव और तनाव के बीच क्षेत्र की एक आशा बहु की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद से अन्य आशा बहुओं में भय और असुरक्षा की भावना और गहराती जा रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न के चलते कुछ आशा बहुएं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई हैं। आशा एवं संगिनी बहुओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र स्थानांतरण की कार्यवाही नहीं की गई, तो सभी आशा एवं संगिनी बहुएं सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करेंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की होगी।

गजनेर व सरवनखेड़ा के चौराहों पर हो रहा अलाव का इंतजार

प्रशासनिक उदासीनता से घास-फूस जलाने को मजबूर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात माती। शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनपद को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन जिले के प्रमुख चौराहों पर ठंड से बचाव की बुनियादी व्यवस्था तक न होना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। गजनेर चौराहे के साथ-साथ सरवनखेड़ा चौराहे पर भी अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे राहगीरों, मजदूरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरवनखेड़ा, गजनेर में ठंड से बेहाल ग्रामीण और राहगीर मजबूरी में घास-फूस, लकड़ी और कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर अस्थायी अलाव जलाकर शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह और शाम के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जब घना कोहरा और सर्द हवाएं लोगों को ठितुरने पर मजबूर कर देती हैं। चौराहों पर खड़े दिहाड़ी मजदूर, ठेला-पटरी

दुकानदार, बुजुर्ग और दूर-दराज से आने-जाने वाले राहगीर ठंड से बचने के लिए इधर-उधर सुलगते अलाव का सहारा लेने को विवश हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष ठंड के मौसम में प्रशासन की ओर से चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की घोर उदासीनता के चलते अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। अस्थायी अलाव के कारण जहां आग लगने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, वहीं उठते धुएं से आवागमन करने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।

ग्रामीणों और राहगीरों ने सवाल उठाया है कि जब शीतलहर को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी है, तो फिर जिले के सबसे व्यस्त चौराहों पर अलाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही ठंड से बचाव के ठोस इंतजाम नहीं किए गए,



तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गजनेर और सरवनखेड़ा चौराहों सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल अलाव की समुचित व्यवस्था कराई जाए।

व्या बोले जिम्मेदार

प्रमारी बीडीओ विमल सचान ने बताया कि सभी ग्राम प्रधान और सचिवों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही अलाव जलवाए जायेगे।

धंसक गई सड़क हादसों का खतरा बढ़ा

» भारी वाहनों की आवाजाही में मुश्किलें, रात में गिरकर घायल हो रहे राहगीर

» लाखों की लागत से बनी सड़क की खुली पोल, ग्रामीणों ने की शिकायत



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा ब्लॉक क्षेत्र में बल्हाराऊ-देवीपुर-मलासा-चांदपुर मार्ग पर बनी सड़क एक साल भी ठीक से नहीं चल पाई और अब जगह-जगह धंसने लगी है। मलासा गांव के निकट सेगुर नदी पुल के पास सड़क धंस जाने से बड़ा गड्ढा बन गया है। इससे हादसों का खतरा बढ़ गया है और भारी वाहनों की आवाजाही तक बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

स्थानीय युवाओं ने बताया कि यह मार्ग कानपुर-झांसी हाईवे के देवीपुर चौराहे से मूसानगर की मुगल रोड को जोड़ता है। इस मार्ग से रोज भारी वाहन गुजरते हैं। पानी के बहाव और घटिया निर्माण सामग्री के चलते फरवरी में शुरू हुआ मरम्मत कार्य जुलाई में पूरा हुआ, लेकिन सड़क पहली बरसात भी नहीं झेल पाई थी अब फिर से धंसकर बड़े गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों के कारण कई बार लोग रात में गिरकर घायल हो चुके हैं। हादसों की आशंका इतनी अधिक है कि फिलहाल गड्ढों के किनारे केवल काटन और पेड़ डालकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। जिम्मेदार विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही कोई स्थायी समाधान निकाला गया।

SIDDHIVINAYAK ENCLAVE

COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL



Fully
Furnished
Flat

- Lift
- Power Backup

For Sale

Ground Floor = Hall (2800sqft.)
1st to 3rd Floor = 3BHK Flat(1550sqft.)

Site Add : Plot No. 600/5, House No. 120/505, Shivji Nagar, Scheme No.1
Kanpur Nagar (Near Shivani Nursing Home)
Near Kanpur Medical Centre Lajpat Nagar, Kanpur

Mob : 9936444099, 7355766844, 9369936943

बुलंदशहर मां-बेटी सामूहिक दुष्कर्म कांड

पांच दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। बुलंदशहर के बहुचर्चित मां-बेटी सामूहिक दुष्कर्म कांड में नौ वर्ष बाद न्याय की बड़ी पहल हुई है। विशेष बाल संरक्षण न्यायालय ने इस जघन्य अपराध में शामिल पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में आज अदालत ने पांचो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह हृदयविदारक घटना 29 जुलाई 2016 की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर हुई थी। उस समय एक परिवार शाहजहांपुर जा रहा था। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास हथियारबंद गिरोह ने उनकी गाड़ी रोक ली और पूरे परिवार को सड़क किनारे बंधक बना लिया। इसके बाद परिवार के सामने ही मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन ही नाबालिग पीड़िता को पहली बार मासिक धर्म आया था, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। इस अमानवीय वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया था।

प्रकरण में पुलिस की गंभीर लापरवाही भी उजागर हुई थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तत्काल आपातकालीन पुलिस सेवा नंबर पर कॉल

वीभत्स घटना क्रम में पांच दरिंदे पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं, एक आरोपी की मौत हो चुकी है



कर सहायता मांगी, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बाद में पीड़िता के पिता ने नोएडा में तैनात अपने एक परिचित पुलिसकर्मी को फोन कर मदद ली। लापरवाही के आरोप में पेट्रोलिंग वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी को निलंबित किया गया था।

उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी।

पुलिस ने मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी सलीम की मृत्यु हो गई। वहीं अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू पुलिस

मुठभेड़ में मारे गए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज और जबर सिंह को क्लीनचिट देते हुए आरोप सूची से बाहर कर दिया था। शेष पांच आरोपियों को अब दोषी ठहराया गया है। विवेचना के दौरान पीड़िता की मां के पेटिकोट पर मिले वीर्य का आरोपियों से मिलान हुआ, जिसे महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य माना गया। आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हथियारों के साथ अपराध, सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतः

संज्ञान लेते हुए जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी थी। इस प्रकरण से जुड़ा एक और चौकाने वाला पहलू तब सामने आया, जब दोष सिद्ध होने के बाद एक अपराधी ने अदालत परिसर में मीडिया से कहा कि उसे प्रसिद्ध कर दिया जाए। यह बयान अपराधियों की मानसिकता और संवेदनहीनता को दर्शाता है।

नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोष सिद्ध होने से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। आज अदालत ने इस मामले में दोषी माने गए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

देह ब्यापार: कमरे में एक लड़की, 5 लड़के

किराये के फ्लैट में देह ब्यापार का भंडाफोड़, युवती समेत पांच युवक गिरफ्तार

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी महेंद्रनगर में किराये के एक फ्लैट में देह ब्यापार संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने रात्रि में छापा मारकर युवती समेत पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महेंद्रनगर स्थित एक फ्लैट में एक युवती कई युवकों के साथ ठहरी हुई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक युवक ने आंशिक रूप से दरवाजा खोलकर बातचीत की। संदेह गहराने पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीतर प्रवेश किया। अंदर कमरे में एक युवती चार युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली, जबकि पास में उतेजक दवाइयां और सुरक्षा साधन भी पाए गए। दरवाजा खोलने



वाला युवक बाहर मौजूद था, इस प्रकार कुल पांच युवक मौके पर मिले।

गिरफ्तार युवकों की पहचान बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बिचपुरी निवासी रोहित, डेलापीर निवासी सोनू, स्टेडियम रोड निवासी बसंत, मिथिलापुर कॉलोनी निवासी अभय विक्रम और कांकर टोला निवासी सुधांशु के रूप में हुई है। इनके साथ एक युवती भी शामिल है, जो इस पूरे मामले की मुख्य कड़ी मानी जा रही

है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रोहित ठाकुर का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है। बताया जाता है कि पीलीभीत बाईपास रोड पर करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में उसने दिनदहाड़े फायरिंग की थी। उस समय वह राजीव राणा नाम के शख्स की तरफ से फायरिंग कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में चुनू पंडित नाम के शख्स ने कार से टक्कर मारकर रोहित की कमर और पैर

तोड़ दिए थे।

रोहित के खिलाफ 19 मुकदमे हैं दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रोहित के खिलाफ करीब 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कई वीडियो और फोटो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अब पुलिस इस देह ब्यापार से अन्य लोगों के जुड़े होने के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह का अपराध करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ में पता चला कि युवती देह ब्यापार में संलिप्त है और उसी ने फ्लैट किराये पर लिया था। युवकों ने उसके पास आने के लिए पच्चीस हजार रुपये दिए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

कोचिंग पढ़ाकर लौट रही शिक्षिका से की छेड़खानी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

बरेली। बरेली में कोचिंग पढ़ाकर लौट रही शिक्षिका से शनिवार शाम इज्जतनगर इलाके में बाइक सवार शोहदे ने छेड़खानी कर दी। शिक्षिका ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी तहसीन रजा खां को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने प्राथमिकता से कार्रवाई की। इज्जतनगर इलाके की एक कॉलोनी निवासी शिक्षिका ने शनिवार रात थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह को बताया कि वह कोचिंग पढ़ाती हैं। शाम के वक्त रोड नंबर सात से घर लौट रही थीं। उसी समय सीबीगंज के खतौला गांव का तहसीन रजा खां बाइक से वहां से गुजरा। आरोप है कि तहसीन रजा ने शिक्षिका के साथ छेड़खानी कर दी। शिक्षिका ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए। इस पर आरोपी भाग निकला। इसके बाद शिक्षिका ने इज्जतनगर थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

इज्जतनगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को आरोपी तहसीन रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ओवरडोज से मौत, कागजों से किया जा रहा बचाव!

» निर्मला हॉस्पिटल केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खोल दी फाइलों की पोल

» मैक्स हॉस्पिटल के दस्तावेजों में किया तारीखों का खेल

» आईएमए की मौजूदगी में मैनेजमेंट का मीडिया पर आरोप

» सील आईसीयू के बावजूद सवाल के घेरे में पूरा मेडिकल सिस्टम

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

उलझता दिखा।

आईएमए के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में निर्मला हॉस्पिटल के मालिक डॉ. बनौधा ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर मृत महिला के इलाज में ओवरडोज के आरोपों को सिर से खारिज कर दिया। लेकिन यही इनकार उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया, जब यह तथ्य



सामने आया कि महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से लिखित रूप में ओवरडोज दिए जाने की स्वीकारोक्ति पहले ही सामने आ चुकी है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया ओवरडोज का आरोप पूरी तरह झूठा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ओवरडोज नहीं दिया गया था तो फिर लिखितस्वीकारोक्ति किस दबाव में और क्यों की गई? क्या यह सच दबाने की कोशिश थी या अब सच से मुकरने का प्रयास?

मौके पर अपमान, मंच से आरोप घटना वाले दिन मौके पर पहुंचे कुछ पत्रकारों ने बताया कि हॉस्पिटल की संचालिका ने कथित तौर पर अपमानित किया। इससे आहत होकर कई पत्रकार खुद को अपमानित महसूस करते हुए लौट गए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल प्रबंधन मीडिया पर अस्पताल की छवि खराब करने का आरोप लगाता नजर आया।

मैक्स हॉस्पिटल के कागजों ने खोल दिया राज

सबसे सनसनीखेज खुलासा तब हुआ, जब डॉ. बनौधा की ओर से मीडिया को दिए गए दस्तावेजों में ही तारीखों का खेल सामने आ गया। मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े कागजात में मरीज के एडमिशन की तारीखें आपस में मेल नहीं खा रहीं। कहीं भर्ती पहले दिखाई जा रही है, तो कहीं रेफरल बाद का बताया जा रहा है। इस गड़बड़ी ने न सिर्फ इलाज की प्रक्रिया, बल्कि रेफरल सिस्टम की साख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या यह महज तकनीकी चूक है या फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए किया गया कागजी प्रबंधन?

सूत्रों का आरोप है कि होटल में पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई। चर्चा यहां तक है कि लिफाफा संस्कृति के सहारे सवालों की धार कुंद करने का प्रयास हुआ। हालांकि, स्वराज इंडिया इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से सवालों से बचा गया, उसने संदेह को और गहरा कर दिया है।

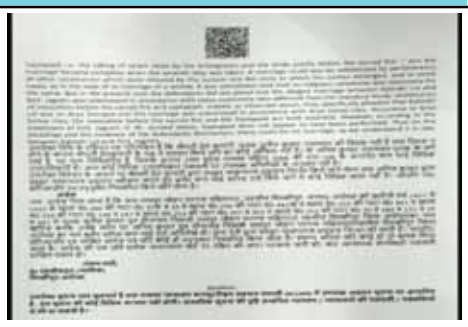
मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएमओ अयोध्या ने निर्मला हॉस्पिटल के बेसमेंट में संचालित आईसीयू को सील कर दिया। यह कार्रवाई यह तो साबित करती है कि अनियमितता थी, लेकिन साथ ही यह भी सवाल छोड़ जाती है—

अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था, तो आईसीयू सील क्यों किया गया? और अगर अनियमितता थी, तो सिर्फ आईसीयू सील कर बाकी अस्पताल क्यों सुरक्षित? ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि ओवरडोज नहीं हुआ, तो लिखित स्वीकारोक्ति क्यों? एडमिशन डेट में हेराफेरी किसके इशारे पर? मैक्स हॉस्पिटल की भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित थी या कागजी खेल का हिस्सा भी? आईएमए की मौजूदगी क्या सिर्फ नैतिक समर्थन थी या ढाल? मामले ने अब पूरे अयोध्या जनपद में अवेध और अर्ध-वेध अस्पतालों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो चुकी है।

अयोध्या। निर्मला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कथित दवा ओवरडोज से महिला की मौत का मामला अब सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं, बल्कि कागजी हेराफेरी, प्रेस मैनेजमेंट और सिस्टम की चुप्पी का हाई-प्रोफाइल उदाहरण बनता जा रहा है। मामले को शांत करने के इरादे से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उल्टा ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया कि अस्पताल प्रबंधन खुद अपने ही दस्तावेजों के जाल में

न्याय मांग रही विधवा, तहसीलदार के आदेश पर उठे सवाल

» महिला का आरोप, पेंशन से जुड़े दस्तावेजों के बाद भी उसे वैध अधिकार नहीं मिले



» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील से जुड़ा एक मामला इन दिनों प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। न्यायिक तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा पारित आदेश को लेकर एक विधवा महिला ने सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी अयोध्या को प्रार्थना पत्र दिया है।

पीड़िता का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार रजिस्टर, आधार, निर्वाचन कार्ड और पेंशन से जुड़े दस्तावेजों के बावजूद उसे उसके वैध अधिकारों से वंचित किया गया। महिला का कहना है कि आदेश पारित करते समय न तो तथ्यों की पूर्ण जांच हुई और न ही प्रस्तुत साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया।

वहीं उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर की रिपोर्ट पर भी पीड़िता ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उसमें उसके पक्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। फिलहाल मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित है और महिला न्याय की आस लगाए बैठी है। अब निगाहें जिलाधिकारी अयोध्या पर टिकी हैं कि क्या मामले में पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर मामला फाइलों में ही रह जाएगा।

खेल प्रतियोगिता में दम दिखाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान

दो दिवसीय विधायक खेल प्रतियोगिता का समापन

» जब हम टीम भावना के साथ कार्य करते हैं, तभी सफलता मिलती है : चंपत राय

» खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का होता है विकास : वेद प्रकाश गुप्ता

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीडा संकुल में आयोजित दो दिवसीय विधायक खेल प्रतियोगिता का समापन रविवार को भव्य रूप से हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, मेडल और कप प्रदान किए। मुख्य अतिथि चंपत राय ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद से मिल-जुलकर काम करने की भावना विकसित होती है। जब हम टीम भावना के साथ कार्य करते हैं, तभी सफलता मिलती है।

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि विधायक खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को मंच देना है। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल सीनियर बालिका वर्ग में डाभासेमर की टीम विजेता रही, जबकि आईएमए उपविजेता बनी। जूनियर वर्ग में भी डाभासेमर विजेता और आईएमए उपविजेता रही। शॉटपुट प्रतियोगिता में जूनियर बालक वर्ग में सूरज सिंह ने प्रथम तथा



अमन कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में दिव्यांशी प्रथम और चांदनी द्वितीय रहीं। सीनियर बालक वर्ग में सागर प्रथम एवं शनि द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि बालिका वर्ग में नेहा ने प्रथम और सोनी ने द्वितीय स्थान हासिल किया।

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को

ट्रैकसूट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समापन सत्र में ब्लाक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, अतुल सिंह, प्रमुख उद्योगपति राकेश लधानी, भाजप नेता अमल गुप्ता, मीडिया प्रभारी दिवाकर



सिंह, दिनेश मिश्रा, दिव्य प्रकाश तिवारी, रवि सोनकर, हेमंत जायसवाल, हरभजन गौड़, दीपक सिंह गम्बर, लाल शुक्ला, नंद कुमार सिंह, वरुण चौधरी, उमाशंकर सिंह मुन्ना ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया।